बैंकिंग के वर्तमान मुद्दे*

रघुराम जी. राजन

मुझे आज यहां आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। एक ऐसे देश में जो 7 प्रतिशत से अधिक की विकास दर से बढ़ रहा हो, जिसमें उद्यमिता का उत्साह भरा हुआ हो, जिसकी आबादी युवा हो और जो मोबाइल टकनालोजी के साथ पली-बढ़ी हो, उस देश के बारे में कोई भी यह नज़रिया रखेगा कि वहां का बैंकिंग क्षेत्र अत्यधिक तीव्रगामी है। हालांकि हाल के समय में बैंकों के शेयर मूल्यों में हुई गिरावट से निवेशक सोच में पड़ गए थे। इसका आंशिक कारण बाज़ार की उथल-पुथल रही है। लेकिन कुछ बैंक के शेयर मूल्यों में अधिक गिरावट आने की सच्चाई यह थी कि उन्होंने अर्थव्यवस्था में अत्यधिक लीवरेज तरीके से खेल खेला था। खराब दिनों में वे और भी नीचे चले गए, अच्छे दिनों में बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए। बाज़ारों में सामान्यतया गिरावट का वातावरण था, इसलिए बैंक शेयर मूल्यों में भी स्पष्ट गिरावट नज़र आई।

लेकिन, इसका कुछ कारण यह भी था कि कुछ बैंकों के परिणाम, खासतौर से सरकारी क्षेत्र के बैंकों के, यदि थोड़ा हल्के से कहें तो अच्छे नहीं थे। इसके लिए स्पष्ट रूप से एक महत्वपूर्ण कारक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा की गई आस्ति गुणवत्ता समीक्षा (एक्यूआर) एवं उसके बाद की स्थिति थी। इसलिए यह समझना उपयोगी होगा कि एक्यूआर का औचित्य क्या है, यह प्रक्रिया क्या है और मेरे हिसाब से ऐसा करने से इसका परिणाम क्या होगा।

दबावग्रस्त ऋणों के संबंध में कार्रवाई करना

जैसाकि आप जानते हैं कि समय बीतने के साथ-साथ अर्थव्यवस्था की अनेक बड़ी परियोजनाओं ने कठिनाइयों का सामना किया है। इसके कारण वही रहे हैं जो आज की सुबह श्री मूंदड़ा ने बताए हैं जैसे - परियोजना का खराब मूल्यांकन, परियोजना में अत्यधिक विलंब, कमज़ोर निगरानी और लागत में वृद्धि और मूल्यों तथा आयात पर विश्व की अतिशय क्षमता का प्रभाव । ऐसी परियोजनाओं को दिए गए ऋण दबावग्रस्त बन गए।

ऋण दबाव के बारे में दो प्रमुख दृष्टिकोण हैं। एक तो यह है कि बैंड-एड लगा दीजिए ताकि ऋण जीवंत बना रहे और यह उम्मीद रखिये कि आने वाला समय और वृद्धि परियोजना को वापस सही पटरी पर ले आएगी। ऐसा कभी-कभी ही होता है। अधिकांश अवसरों पर धीमी वृद्धि जो दबाव को बढ़ा देती है, बनी रहती है। मूल ऋण की धारा को बनाए रखने के लिए नया उधार बढ़ता रहता है। भारी कर्ज़ में डूब जाने और वापस न कर पाने की स्थिति में प्रवर्तन की दिलचस्पी समाप्त हो जाती है, वह वर्तमान समस्या के दायित्व निर्धारण के बारे में थोड़ा-बहुत ही कर पाता है और परियोजना अधिक नुकसान में चली जाती है।

इसके लिए एक वैकल्पिक दृष्टिकोण यह है कि दबावग्रस्त परियोजना को वापस पटरी पर लाए जाने का प्रयास किया जाए न कि बैंड-एड लगाया जाए। ऐसा करने के लिए गहरी सर्जरी करनी पड़ेगी। बदली हुई परिस्थितियों को देखते हुए ऋण को जब वे स्वीकृत किए गए थे तब उसमें से मूल्यह्रास को घटाना पड़ेगा। यदि ऋण में से मूल्यह्रास को निकाल दिया जाता है तो प्रवर्तक और अधिक इक्विटी लाएंगे, और अन्य हितधारक जैसे टेरिफ अथारिटी या स्थानीय सरकार उसमें योगदान देगी और परियोजना के दुबारा जीवंत हो उठने का पूरा मौका होगा तथा प्रवर्तक को प्रोत्साहन मिलेगा कि वह परियोजना को वापस पटरी पर लाने के लिए अपना अधिकतम प्रयास करेगा।

लेकिन, गहरी सर्जरी करने के लिए जैसे पुनर्रचना करना या ऋण में से मूल्यह्रास को घटाकर कम करना, अर्थात् बैंक को यह मानना पड़ेगा कि उसके यहां समस्या है - कि उस आस्ति को अनर्जक आस्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत करे। अतः एनपीए के रूप में वर्गीकरण को निश्चेतक के समान मानें जिससे आवश्यक गहन सर्जरी करने की स्थिति में होगा और परियोजना को वापस उसके पैरों पर खड़ा कर सकेगा। यदि बैंक यह दिखाना चाहते हैं कि ऋण की स्थिति ठीक है, तो फिर बैंड-एड लगाया जा सकता है - उसके बाद और भी कड़ी कार्रवाई के लिए एनपीए वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ेगी।

ऋण का वर्गीकरण महज अच्छी लेखांकन प्रणाली है - इससे पता चलता है कि ऋण का सही मूल्य क्या होगा। इसके साथ-साथ प्रावधान जुड़ा होता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि बैंक बफर के रूप में राशि अलग रखता है जो संभावित नुकसान को पचा लेता है। यदि नुकसान नहीं होता है तो बैंक प्रावधान की गई रकम को वापस लाभ में जोड़ सकते हैं। यदि नुकसान हो ही जाता है तो ऐसी स्थिति में बैंक को तुरंत बहुत बड़ा नुकसान हो जाने की घोषणा नहीं करना चाहिए, वह विवेकपूर्ण तरीके से किए गए प्रावधान को हुए नुकसान के साथ समायोजित कर सकता है। इस प्रकार बैंक का तुलनपत्र बैंक की

* डॉ. रघुराम जी. राजन, गवर्नर. भा.रि.बैंक द्वारा 11 फरवरी 2016 को मुंबई में आयोजित सीआईआई के प्रथम बैंकिंग सम्मेलन में दिया गया भाषण।

उचित एवं सुदृढ़ तस्वीर प्रस्तुत करेगा, जैसाकि बैंकों के तुलनपत्रों से अपेक्षा की जाती है। निःसंदेह, हम रेगुलेटरी नरमी लेते हुए उसकी गणना के दिन को स्थगित कर सकते हैं। लेकिन जब तक उद्योग की स्थिति में अचानक ड्रामाई अंदाज़ में सुधार नहीं आता है, तब तक बैंक के तुलनपत्र की सुदृढ़ स्थिति बिखरी हुई रहेगी और अंततः वह गड्ढा और बड़ा होता जाएगा।

वर्ष 2008-09 में विश्व में आए संकट के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक ने कतिपय स्वरूप के दबावग्रस्त ऋणों की पुनर्रचना में नरमी बरतने की सहमति दे दी थी, इस उम्मीद में कि यह एक अस्थायी आवश्यकता है जिसकी मज़बूत संवृद्धि के लिए ज़रूरत है। दुर्भाग्य से, अनेक कारणों से, दबाव अस्थायी नहीं था, और इन क्षेत्रों में वृद्धि भ्रांतिपूर्ण रही। इसलिए, इस प्रक्रिया के प्रारंभ में रिज़र्व बैंक ने बैंकों को टूल्स दिए कि वे दबावग्रस्त ऋणों के संबंध में कार्रवाई कर लें, साथ ही यह भी जानकारी दी कि उधारकर्ताओं ने प्रणाली से कुल मिलाकर कितना कर्ज लिया है तथा परियोजना के वित्तीय दबाव को कम करने के लिए अधिक कारगर तरीके बताए जैसे संयुक्त उधारदाता मंच, रणनीतिक ऋण पुनर्रचना पद्धति, तथा 5/25 प्रणाली। एक प्रकार से रिज़र्व बैंक ने कार्यशील समाधान प्रक्रिया सृजित करने की कोशिश ऐसी स्थिति में की जब मौजूदा बैंकरप्सी प्रणाली बहुत खराब तरीके से कार्य कर रही थी।

आस्ति गुणवत्ता की समीक्षा

यह ठीक है कि प्रत्येक नये टूल का इस्तेमाल किसी समस्या के निदान के लिए किया जाना चाहिए लेकिन इसके विपरीत उसका उपयोग समस्याओं से बचने के लिए भी होना चाहिए। इस प्रकार बैंकों को टूल प्रदान करने के बाद रिज़र्व बैंक ने अप्रैल 2015 में रेगुलेटरी नरमी समाप्त कर दी और आस्ति गुणवत्ता की समीक्षा (एक्यू आर) प्रारंभ की ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि बैंक अपने तुलनपत्रों को साफ-सुथरा बनाने में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। बैंकों के साथ काम करते हुए हमारे पर्यवेक्षक, जो हमारे बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग की प्रमुख सुश्री पार्वती वैरवसुंदरम, हमारे पर्यवेक्षण पोर्टफोलियो की कार्यपालक निदेशक सुश्री मीना हेमचंद्र और निश्चित ही हमारे उपगवर्नर श्री एस.एस.मूंदडा के उत्तम नेतृत्व में ऐसे ऋणों का पता लगाया है जिनकी स्थिति चिंताजनक है तथा उनमें अत्यधिक दुर्बलताएं हैं। चिंताजनक ऋणों के बारे में बैंक उन्हें नियमित बनाने के लिए उन्हें वापस पटरी पर लाने का प्रयास कर रहे हैं और उन्हें उस श्रेणी में वर्गीकृत कर रहे हैं जिनकी गहन सर्जरी नहीं की जानी है - और ऋण में मौजूदा दबाव की मात्रा को ध्यान में रखते हुए प्रावधान कर रहे हैं। वे उन ऋणों के संबंध में भी प्रावधान कर रहे है जिनमें कमज़ोरियां हैं। हमारा इरादा है कि मार्च 2017 तक बैंक के तुलनपत्र साफ-सुथरे बन जाएं और उनमें पूरी तरह से प्रावधान किया गया हो।

क्यों नहीं यह सारी क़वायद एक ही बार में कर ली जाती है, क्यों इसे छह तिमाही में किया जाएगा? स्पष्ट है कि इन ऋणों में से कई ऋण ऐसे हैं जिन्हें नियमित बनाया जा सकता है या उन्हें स्थायित्व प्रदान किया जा सकता है भले ही वे कमजोर क्यों न हों लेकिन रेगुलर हों, इसे सही सामूहिक कार्रवाई से संभव बनाया जा सकता है। कभी-कभी एनपीए वर्गीकृत हो जाने पर उसकी गहरी सर्जरी की अनुमति दे दी जाती है, इससे बैंक के बोर्डों को जोखिम न उठाने को बढ़ावा मिलता है और वे उधार देना बंद कर देते हैं भले ही परियोजना फायदेमंद हो। हमें इस प्रकार के दृष्टिकोण से बाहर निकलना होगा - हमने परिपत्र जारी किया है जिसमें यह लिखा गया है कि किसी ऐसी परियोजना को यदि ऋण दिया जाता है जिसके अन्य ऋण एनपीए हैं, तो इसका मतलब यह नहीं होता है कि अब दिया गया ऋण स्वतः एनपीए हो जाएगा - उसे एनपीए बनने में समय लगेगा। ऐसा तब तक नहीं हो पाएगा जब तक इस संबंध में मनोवृत्ति नहीं बदलेगी, यह तभी होगा जब बैंक एनपीए के समस्त मूल्य दिखाएंगे, जिसके लिए हम उनके साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं ताकि क्रमशः यथोचित कार्रवाई तुरंत की जा सके। लेकिन, इस खेल का हश्र सभी को पता है और वो होकर रहेगा। हम एक के बाद एक एक्यू आर नहीं करना चाहेंगे।

निष्पादित किए जाने वाले कार्य के उद्देश्य का संकेत दे दिए जाने के बाद हमारी टीम बैंकों के साथ कार्य कर रही है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी बैंक मोटे तौर पर निर्धारण एवं प्रावधानीकरण के मामले में समान स्तर पर हैं, भले ही प्रत्येक बैंक में मामला-दर-मामला थोड़ा लचीलापन हो। इसका आशय यह है कि समस्त बैंकों के दिसंबर 2015 तिमाही के परिणामों की तुलना की जा सकती है ताकि प्रत्येक बैंक द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कार्यों का मोटे तौर पर अंदाज़ा लगाया जा सके। कुछ बैंकों ने यह इरादा ज़ाहिर किया है कि वे इस संबंध में तेजी से आगे बढ़ना चाहेंगे ताकि वे समस्याओं को पीछे छोड़ दें, और हमने इसके लिए उन्हें नहीं रोका है। हमने इस बारे में कोई अंतिम अनुमान नहीं दिया है क्योंकि हमारा मानना है कि इस संबंध में लक्ष्य बदलते रहने वाले हैं, जिसमें अधिक बैंक कार्रवाई, प्रवर्तकों का बेहतर रेस्पांस होगा जिससे वृद्धि होगी और अंततः लागत घटेगी। यह याद दिलाना ज़रूरी है कि इन समस्त दबावग्रस्त ऋणों में से कई आर्थिक रूप से फायदेमंद उत्पादनशील आस्ति हैं, न कि भूत-बंगला।

इस समीक्षा में बहुत सा कार्य किया जा चुका है, जिसमें प्रत्येक स्तर पर सरकार के साथ एवं उच्चतर स्तर पर कई बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। इसमें सरकार की पूरी सहभागिता और समर्थन था। हमने संभावित परिणामों के आधार पर अनेक प्रकार के परिदृश्य (सेनेरियोज) को मैप किया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि वे सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए आवश्यकतानुसार पूंजी प्रदान करने में मदद करेंगे। हमारा मानना है कि सरकार द्वारा दिया गया समर्थन पर्याप्त है। हमारे विभिन्न परिदृश्यों (सेनेरिओज) से पता चलता है कि इस प्रकार की एक्सरसाइज से निजी क्षेत्र के बैंकों को रेगुलेटरी पूंजी की आवश्यकता नहीं होगी। अंततः, रिज़र्व बैंक, बैंकों की ऐसी पूंजी की पहचान करने के बारे में कार्य कर रहा है जिनका वर्तमान में निर्धारण नहीं किया जा सका है जैसे - ऐसी आस्तियां जिनका मूल्य कम आंका गया है। रिज़र्व बैंक इन आस्तियों की गणना बासेल मानदंडों के अनुसार पूंजी में करने की अनुमति दे सकता है बशर्ते बैंक न्यूनतम सामान्य इक्विटी मानकों को पूरा करे।

कुछ वित्तीय विश्लेषकों ने यह बढ़-चढ़कर दावा किया है कि दबावग्रस्त आस्तियों की समस्या काफी विकराल है। यह अत्यधिक भयभीत करने वाली बात है। हमारा अनुमान है कि किसी भी पुनः पूंजीकरण सुविधा की अनुपलब्धता की स्थिति में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की अल्प संख्या द्वारा न्यूनतम मुख्य पूंजी अपेक्षा का किसी भी प्रकार के उल्लंघन का असर बहुत छोटा होगा। उनके लिए सरकारी इक्विटी की जरूरत पड़ेगी या प्रिफ्रेंस शेयर डालने होंगे क्योंकि वे कुछ इस प्रकार के बैंक है जिनके लिए बाज़ार से इक्विटी जुटाना कठिन है। कुछ अन्य बैंक भी हैं जिन्हें उनकी पूंजी में थोड़ी पूंजी और डालने की आवश्यकता है ताकि इत्मीनान रहे कि उनके पास न्यूनतम पूंजी से ऊ पर यथोचित बफर है। सरकार ने पहले ही स्पष्ट रूप से प्रतिबद्धता दर्शाई है जो हमारे विचार से समस्त परिदृश्य को संभाल लेगी, और की वचनबद्धता है कि चाहे जिस सीमा तक हो वह अपने बैंकों की सहायता के लिए उनके पीछे खड़ी है। रिज़र्व बैंक किसी भी बैंक को उसकी ज़रूरत के हिसाब से चलनिधि उपलब्ध कराएगा। हालांकि हमें किसी भी प्रकार की चलनिधि संबंधी कमी नज़र नहीं आ रही है।

संक्षेप में, संभव है कि थोड़े समय के लिए कुल बैंकों की लाभप्रदता प्रभावित हो, लेकिन एक बार संपूर्ण प्रणाली साफ-सुथरी हो जाने के बाद वह आर्थिक विकास में मददगार होगी जिसे कायम रखा जा सकेगा और जो लाभप्रद होगा। हमारे सरकारी क्षेत्र के बैंकों की आर्थिक आस्तियां जैसे लोगों में उनके प्रति भरोसा, उनके ज्ञानी कर्मचारी, उनका कार्यस्थल कहां है तथा उनकी पहुंच कितनी है और कम लागत पर उनके यहां निधि की उपलब्धता ये सब होने से उनका पूरा-पूरा उपयोग किया जा सकेगा।

अब क्यों ?

अब क्यों ? हमने बैंकों को साफ-सुथरा बनाने के लिए ऐसा समय क्यों चुना है जब विश्व के बाजारों में उथल-पुथल मची हुई है ? क्यों नहीं विकास को इस समस्या का निदान करने दिया जाए ? जैसाकि मैंने कहा कि उक्त प्रक्रिया अप्रैल 2015 से प्रारंभ हो चुकी थी। हमें उस समय यह ज्ञात था कि आगे चलकर विश्व की अर्थव्यवस्था कमज़ोर बनी रहेगी लेकिन यह अंदाज़ा नहीं था कि बाज़ारों में आज इतनी उथल-पुथल रहेगी। जो भी हो, यह हमारे विश्वास को मज़बूत करता है कि जब हमने ठान ही लिया है तो हमें करके दिखाना है।

जहां संवृद्धि की दर प्रणाली के लिए मददगार साबित होगी, वहीं यह काफी हद तक उसे बाधित कर सकती है यदि साफ-सुथरा बनाने की प्रक्रिया नहीं पूरी की गई। सरकारी क्षेत्र के बैंकों में खाद्येतर ऋण में वृद्धि, जो प्रणाली का सबसे अधिक दबावग्रस्त हिस्सा है, कैलेंडर वर्ष 2015 में केवल 6.6 प्रतिशत बढ़ा है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों में औद्यागिक ऋण की वृद्धि केवल 3.3 प्रतिशत थी जबकि कृषि और संबद्ध गतिविधियों को दिया गया उधार 10.4 प्रतिशत था। एक मात्र मज़बूत क्षेत्र वैयक्तिक ऋण का था, जिसमें वृद्धि 16.9 प्रतिशत थी। इसके विपरीत, निजी क्षेत्र के बैंकों की खाद्येतर ऋण वृद्धि 20.2 प्रतिशत, कृषि में 25.4 प्रतिशत, उद्योग में 14.6 प्रतिशत तथा वैयक्तिक ऋण में 23.5 प्रतिशत वृद्धि थी। दूसरे शब्दों में, वैयक्तिक ऋण को छोड़कर इन समस्त क्षेत्रों में निजी क्षेत्र के बैंकों में वृद्धि सरकारी क्षेत्र के बैंकों की तुलना में 10 प्रतिशतता बिंदु अधिक थी जबकि वैयक्तिक ऋण में वृद्धि 6.6 प्रतिशतता बिंदु अधिक थी।

मेरे पास सबसे बेहतर व्याख्या यह है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों का तुलनपत्र प्रबंधन का ध्यान आकर्षित किए हुए है और उन्हें रोक रखा है, और उनके पास एक ही रास्ता है जिससे कि वे अर्थव्यवस्था की ऋण आवश्यकताओं के लिए ऋण की आपूर्ति कर सकें, जो उच्च आर्थिक वृद्धि के लिए अनिवार्य है, अपने तुलनपत्र को साफ-सुथरा बनाएं। ऋण की धीमी वृद्धि में जो निहित संदेश है वह यह है कि बैंकों ने विस्तारित समग्र तुलनपत्र में दबावग्रस्त आस्तियों के आकार को कम करने के प्रयास में उधार वाजिब तरीके से नहीं दिया है, और इससे भविष्य में फिसलने की संभावना है। संक्षेप में यदि यह प्रश्न पूछा जाए कि पहले सफाई या वृद्धि। तो मेरे हिसाब से स्पष्ट उत्तर है कि पहले सफाई की जाए। वस्तुतः यही सबक हर उस देश से मिला है जहां वित्तीय दबाव की परेशानी का सामना किया गया है।

कुछ नागरिक नुकसान के आकार को लेकर क्रोधित होते हैं, उसे अंततः एबजार्ब किया जाना होगा और चाहते हैं कि ऐसा करने वालों को न्याय के कटघरे में लाया जाए। मैं यह बताना चाहता हूँ कि समस्त एनपीए गलत इरादे से नहीं हैं। उनमें से अधिकांश नहीं हैं। कोई भी ऋण अशोध्य हो सकता है भले ही प्रवर्तक के इरादे नेक हों और बैंक ऋण स्वीकार करने से पहले सभी प्रकार की सावधानी बरत चुका हो। जो भी हो, जहां कहीं भी प्रवर्तक द्वारा अपराध के साक्ष्य हों वहां बेहद ज़रूरी है कि उसके विरुद्ध पूरा कानून खड़ा हो, भले ही बैंक उस परियोजना को और उसपर निर्भर रहने वाले कामगारों को वापस पटरी पर लाने के लिए भरसक प्रयास क्यों न करे। यही कारण है कि हमने धोखाधड़ी पकड़ने एवं निगरानी प्रणाली को सुदृढ़ बनाया है और उम्मीद करते हैं कि बैंक इसे प्रभावी बनाने में अपना समर्थन प्रदान करेंगे।

सरकार रुकी हुई दबावग्रस्त परियोजनाओं को दुबारा चलाने के लिए सीधे-सीधे कार्रवाई कर रही है और रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर कर रही है तथा राष्ट्रीय निवेश एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर निधि के माध्यम से इक्विटी प्रदान करके मदद करना चाहती है। निजी खिलाड़ी जिन्हें फंड की पर्याप्त उपलब्धता है वे आस्तियों को खरीदना चाहते हैं और हमने हाल के सप्ताहों में देखा है कि कुछ प्रवर्तक आस्तियां बेचकर धन जुटाना चाहते हैं ताकि बैंकों को अदा कर सकें या परियोजनाओं में लगा सकें। इन समस्त गतिविधियों का प्रयोजन सफलतापूर्वक सफाई करने से है।

बैंक प्रबंधन और गवर्नेंस में सुधार लाना

हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि हम इस प्रकार की परिस्थितियों का दुबारा सामना न करें। सरकार ने इंद्रधनुष पहल के माध्यम से यह स्पष्ट संकेत दे दिया है कि वह यह चाहती है कि एक बार सरकारी क्षेत्र के बैंक स्वस्थ हो जाएं, तो हमेशा के लिए स्वस्थ बने रहें। बोर्ड को मज़बूत बनाना, प्रबंधन को प्रोत्साहित करने के तरीके तलाशना, ये सब मिलकर ऋण के मूल्यांकन, निगरानी और उनकी चुकौती को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। बैंक अपनी प्रक्रियाओं की समीक्षा अवश्य करें ताकि वे यह सुनिश्चित कर सकें कि वे ऋण के बारे में सही निर्णय ले सकते हैं। नया बैंकरप्सी कोड, पारित हो जाने पर अंततः उधारदाता को एक रास्ता प्रदान करेगा कि वह एक उचित समय में न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से अपना धन वापस प्राप्त कर सकेगा। इसलिए मुझे उम्मीद भी है और विश्वास भी कि अगला समय सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए अलग होगा - वे इस सफाई से और भी सुदृढ़ एवं अधिक सक्षम होकर उभरेंगे।

चलनिधि

अब मैं अंतिम मुद्दे की बात करना चाहूँगा जो एक्यू आर से संबंधित नहीं है बल्कि संपूर्ण प्रणाली में व्याप्त चलनिधि के बारे में है। भारतीय रिज़र्व बैंक प्रणाली में प्रचुर मात्रा में चलनिधि डालता रहा है ताकि सरकारी बैंलेंस में किसी भी प्रकार के मौसमी असंतुलन को समायोजित किया जा सके। वस्तुतः कई दिन तो ऐसा हुआ है कि चलनिधि डालने से मुद्रा बाज़ार की दरें ड्रामाई अंदाज में गिर गई थीं। फिर भी बाज़ार के सहभागियों की शिकायत थी कि बाज़ार में चलनिधि कम है।

हमने बाज़ार के अनेक सहभागियों को रिज़र्व बैंक में बुलाया था कि वे अपनी चिंताओं के बारे में चर्चा करें। हमारी अभी भी यही कोशिश है कि उनकी जो भी जायज़ चिंता है उसे दूर किया जाए, इसीलिए आज हम एक मुद्दे पर कार्रवाई कर रहे हैं जिसे हमने संज्ञान में लिया है, कि चलनिधि कवरेज अनुपात की जरूरत को पूरा करने के लिए किस प्रकार से एसएलआर बाण्ड का इस्तेमाल किया जाए। यद्यपि इस संबंध में परिपत्र बनाने का कार्य चल रहा था, तब भी हमने उसे जारी करने में शीघ्रता की क्योंकि हमें सहभागियों से जो सुनने को मिल रहा था हमने उसे ध्यान में रखा था। अब से हम बैंकों को एलसीआर अपेक्षा को पूरा करने के लिए उनकी एसएलआर होल्डिंग्स से 3 प्रतिशतता बिंदु अधिक रखने के लिए अनुमति देंगे। इस संबंध में और विस्तृत घोषणा आज की शाम में की जाएगी।

समापन

बाज़ार में उथल-पुथल की स्थिति गुज़र जाएगी। तुलनपत्रों की सफाई हो जाएगी और भारतीय बैंक स्वस्थ अवस्था में आ जाएंगे। जहां हमें इस कार्य के विभिन्न आयामों को हलके से नहीं लेना है वहीं हमें यह विश्वास रखना होगा कि यह कार्य किया जा सकता है और सरकार तथा भारतीय रिज़र्व बैंक वह सभी कदम उठाएंगे जिससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि बैंक आगामी समय में अत्यधिक संवृद्धि हासिल करने के लिए मददगार साबित होंगे। धन्यवाद।